

संपादकीय

आधी-अधूरी शिक्षा

विकास और प्रगति के तमाम दावों के बीच यदि देश के करीब आधे स्कूल कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से वंचित हों, स्कूल बंद रहे हों और दाखिले कम हो रहे हों, साथ ही विद्यार्थियों का बीच में पढ़ाई छोड़ने का आंकड़ा बढ़ रहा हो, तो इसे एक बड़ी चुनौती माना जाना चाहिए। निस्संदेह, आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता होता है, लेकिन यदि बुनियादी शिक्षा तमाम विसंगतियों से जूझ रही हो तो विकास की सार्थकता पर सवाल उठेंगे। सवाल खासकर वंचित समाज के बच्चों का है, जिनका बड़ा संघर्ष जीवन-यापन की प्राथमिकताओं से जुड़ा है। स्वतंत्र भारत में शैक्षिक सुधार के जो प्रयास हुए,उनका लाभ वंचित समाज को काफी अधिक हुआ है। दरअसल, सरकारी स्कूल समाज के कमजोर वर्ग की आशा के केंद्र रहे हैं। यदि आज इन समाजों के बच्चे ही शिक्षा से दूर हो रहे हैं, तो तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज भी लाखों बच्चे शिक्षा पाने से वंचित हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे खासे चौंकाने वाले हैं। समीक्ष्य वर्ष 2023–24 की रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले साल के मुकाबले स्कूल में दाखिलों में 37.5 लाख की कमी आई है। जहां वर्ष 2022–23 में स्कूलों में 25.17 करोड़ विद्यार्थी दर्ज थे, वहीं 2023–24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर का है। वहीं समीक्ष्य अवधि में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जिनमें छात्राएं, वंचित व कमजोर वर्ग के बच्चे अधिक हैं। ऐसे में मंथन की जरूरत है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के तमाम प्रयासों, नई शिक्षा नीति लागू होने, अधिक स्कूल खुलने के बावजूद छात्रों के दाखिले में कमी क्यों आ रही है। सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के अंतर को संबोधित करने की जरूरत है। ताकि नये दाखिलों को प्रोत्साहन मिले और छात्र भी बीच में स्कूल न छोड़ें। दरअसल, जरूरत इस बात की भी कि जहां एक ओर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, वहीं स्कूलों में दाखिले को लेकर छात्रों का आकर्षण भी बना रहना चाहिए। साथ ही शिक्षा को व्यावहारिक बनाने और समय के साथ कदमताल करने की जरूरत है। वहीं दूसरी शिक्षा मंत्रालय के प्लेटफॉर्म, युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के यह तथ्य चिंता बढ़ाने वाले हैं कि अभी तक कुल 57 फीसदी स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा मौजूद है। वहीं दूसरी ओर 53 फीसदी स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे दौर में जब ऑनलाइन पढ़ाई का खासा जोर है तो ये बच्चे भविष्य में निजी स्कूलों के छात्रों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उनका क्या भविष्य होगा? विदंबना यह है कि वंचित समाज व कमजोर वर्ग के परिवारों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके पास न तो कंप्यूटर है और न ही स्मार्ट फोन। दरअसल, उनके परिवारों के जीवन यापन का संघर्ष इतना बड़ा है कि कंप्यूटर व स्मार्ट फोन उनकी प्राथमिकता नहीं बन सकते। चिंता की बात यह है कि निम्न मध्यवर्गीय लोग तो निजी स्कूलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, लेकिन कमजोर वर्ग के विद्यार्थी कहां जाएंगे? दरअसल, मौजूदा दौर में सिर्फ साक्षरता से खुश नहीं हुआ जा सकता, जरूरत गुणवत्ता की शिक्षा की भी है। ताकि स्कूल से निकलकर विद्यार्थी देश-दुनिया के साथ कदमताल कर सकें। मंथन इस बात को लेकर भी होना चाहिए कि क्यों लाखों बच्चे स्कूलों की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर क्यों छात्र स्कूल में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं? शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब सामाजिक विसंगतियां दूर होंगी। यहां सवाल स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों के अनुपात का भी है। यह ठीक है कि स्कूलों के भवनों के स्तर में सुधार हुआ है, स्कूलों में बिजली, पानी व जेंडर अनुकूल शौचालय बने हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल स्कूलों में संरचनात्मक विकास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शैक्षिक वातावरण भी स्कूलों की पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए।

दिल्ली का अगला मुत्त्वमंत्रौ

संतोष
चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को बतौर सीईसी अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही अपने ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोपों का भी एक-एक करके जवाब देने की कोशिश की। दिल्ली में इस बार मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 है जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 71 लाख 73 हजार 952 है। जाहिर तौर पर, देश के कई अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिला मतदाता, चुनावी जीत-हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली की चुनावी लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। देश की राजध् ानी दिल्ली में 5 फरवरी को होने जा रहे मतदान में मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव, उनके अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण राज्य- पंजाब में सरकार होने के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली का केजरीवाल के लिए अपना महत्व है। अगर केजरीवाल दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो आम आदमी पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी उनका दबदबा कमजोर होता चला जाएगा। घोटाले के आरोप में जेल तक की यात्रा करने वाले अरविंद केजरीवाल यह बखूबी जानते और समझते हैं कि दिल्ली की हार एक बार फिर से उन्हें राजनीतिक रूप से अछूत बना देगी। क्योंकि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही मजबूरी में कई राज्यों में आप के साथ गठबंधन किया था लेकिन सच्चाई तो यही है कि सोनिया गांधी इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल पर कतई भरोसा नहीं करती है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और गांधी परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 2020 में, दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को सिर्फ 4.26 प्रतिशत मत मिला था और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने नई दिल्ली विध ानसभा सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत हुई है और अब अगर कांग्रेस अपने उस छीने हुए वोट बैंक के छोटे से हिस्से को भी वापस लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर केजरीवाल सहित आप के सभी उम्मीदवारों के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 53.57 प्रतिशत मत के साथ आप को 62 सीटें मिली थी जबकि 38.51 प्रतिशत मत पाने के बाद भी भाजपा के खाले में सिर्फ 8 सीटें ही आ पाई थी। आप और भाजपा के बीच 14.06 प्रतिशत का अंतर था। अगर कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मत प्रतिशत में 8–10 प्रतिशत का भी इजाफा कर पाती है तो फिर दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है

विचार

उत्पादकता बढ़ाने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी

डॉ. संजय

इफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति के उस बयान पर देश में खूब बहस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए युवाओं को ज्यादा समय तक जीतोंड़ मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में निजी कंपनियों में कंपनी के उसूलों के साथ-साथ अफि ाकारियों के हर आदेश का पालन करने और जरूरत से कई गुना ज्यादा काम करने के बदले मामूली वेतनवृद्धियों और छुट्टियों में कटौती आदि के प्रश्न अक्सर विमर्श में रहते हैं। इस पर भी कंपनियों के मालिक और हुक्मरान इसे लेकर जब-तब कोई उपदेश लेकर हाजिर हो जाते हैं कि कर्मचारियों को काम कितना करना चाहिए, दबाव कितना सहना चाहिए और छुट्टियां लेते हुए जीवन और काम में संतुलन कैसे बिठाना चाहिए। इस कड़ी में अडानी समूह के चेयरमैन ने हाल ही में बयान दिया है कि यह संतुलन (वर्क-लाइफ) तब होता है, जब आप अपना पसंदीदा काम करते हैं। बहरहाल, नौकरियों में बढ़ते तनाव और कार्य संस्कृति में बदलाव की जितनी बातें आज हमारे देश में कही-सुनी जा रही हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने और दुनिया की ताकतवर कंपनियों से आगे निकलने का दबाव भारतीय कंपनियों पर काफी बढ़

न्याय प्रणाली

डॉ. सुधीर

भारतीय न्याय संहिता, 2023 एक ऐतिहासिक पहल है जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 को बदलने के लिए लाया गया है। यह संहिता भारतीय न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का वादा करती है। लेकिन क्या यह वास्तव में न्याय प्रणाली में क्रांति ला पाएगी? भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए राजद्रोह का अपराध परिभाषित करती थी। यह धारा उन लोगों को दंडित करती थी जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष फैलाने का प्रयास करते थे। इस कानून के आलोचकों का मानना ​​था कि इसका अर्थ दुरुपयोग किया जाता था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। संहिता ने राजद्रोह के अपराध को निरस्त कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोह के अपराध

गया है। इस दबाव का नतीजा है कि कभी तो इन कंपनियों के संचालक हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करने की जरूरत रेखांकित करते हैं, तो कभी नौकरी में तनाव की बात स्वीकार करने पर उन्हें काम से ही हटा देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। देश-दुनिया में आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो राष्ट्र निर्माण के लिए जुनून की हद तक जुटने के पक्ष में हैं। यह पूरा विमर्श सिर्फ आबादी बहुल देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे विकसित आबादी बहुल देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे विकसित मुल्कों में भी ऐसी ही जुनूनी कार्य संस्कृति की मांग उठ रही है, ताकि वहां की अर्थव्यवस्थाओं का सुदृढ़ विकास हो सके और उद्योग व रोजगार क्षेत्र के संकटों को दूर किया जा सके। कुछ ही अरसा पहले, नोएडा की एक सैलून कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच कामकाजी माहौल के बीच तनाव पैदा होने संबंधी सर्वेक्षण कराया। सौ से ज्यादा कर्मचारियों ने सर्वेक्षण में स्वीकार किया कि कामकाजी दबाव के कारण वे तनाव में हैं, तो उन कर्मचारियों को नौकरी से ही निकालने का दावा किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंसले की आलोचना के महेनजर कंपनी ने सफाई दी कि सर्वेक्षण का मकसद कार्यस्थल पर दबावों और तनावों से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना था। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने तनाव की बात कही है, उन्हें तनाव-मुक्ति नीति (डि-स्ट्रेस

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की

को हटाकर उसके स्थान पर नए अपराधों को परिभाषित किया है। ये नए अपराध देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित हैं। इनमें शामिल हैं लोगों के बीच फूट डालने का प्रयास, शस्त्र प्रदर्श या हिंसा को भड़काना, अलगाववादी गतिविधियां, राजद्रोह कानून के निरसन को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नए कानून का दुरुपयोग न हो। संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कड़ा कर दिया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा बढ़ा दी गई है। साथ ही, कुछ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया

नक्सलवाद को खत्म करने के तमाम दावों के बीच छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर लहलुहान

अजय सोमवार को बस्तर में बीजापुर जिले में नक्सलियों ने फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक ऑपरेशन से लौट रहे जिला रिजर्व गार्ड के एक वाहन को आईईडी का इस्तेमाल कर नक्सलियों ने उड़ा दिया। जिला रिजर्व गार्ड या डीआरजी राज्य पुलिस की एक इकाई है और इसमें ज्यादातर स्थानीय आदिवासियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भर्ती किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने इस बार अपने ही पूर्व साथियों और उन निर्दोष स्थानीय आदिवासियों को निशाने पर लिया है, जो दो पार्टों में फंसे हुए हैं। सुरक्षा और जांच एजेंसियों की निगाहें उन पर रहती हैं और वहीं नक्सली उन पर संदेह की निगाह रखते हैं। सोमवार को हुए नक्सली हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर की शहादत हुई है। हमला बीजापुर जिले के बेदरे-कूटरु रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जवानों का वाहन कई मीटर ऊपर उछल गया और जमीन में 8-10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ९ ामाके के बाद शव और गाड़ी के टुकड़े 20 फीट के दायरे में बिखर गए। अधिकारियों का कहना है कि आईईडी काफी पुराना था और उस पर घास उग आई थी। विस्फोट में उड़े बारुद की गंध अभी हवा में बिखरी हुई है और इधर घटना पर घिसी-पिटी प्रतिक्रियाओं और

आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। साय ने कहा, श्क्सली हताशा में कायरतापूर्ण कृत्य कर रहे हैं। वे बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों से निराश हैं। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रबीजापुर (छत्तीसगढ़) में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूं। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। इससे पहले जब 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर-सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 21 जवानों की शहादत हुई थी, तब भी श्री शाह ने कहा था कि नक्सलियों को सही वक्त आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले साल अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाए का दावा किया था। खुशी की बात है कि वे अब भी अपने इस दावे पर कायम हैं। हालांकि इससे पहले 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री

पॉलिसी) के तहत कुछ समय आराम करने के लिए छुट्टी और अन्य सहुलियतें दी गईं, ताकि वे नई ऊर्जा से काम में जुट सकें। बहुत मुमकिन है कि नोएडा की कंपनी का सर्वेक्षण, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उस कंपनी के प्रति उपजा आक्रोश एक सोची-समझी प्रचार की रणनीति (पब्लिसिटी स्टंट) हो। पर यह सच है कि भारतीय कंपनियों के संचालकों में यह अवधारणा बहुत अंदर तक पैठी हुई है कि उनके देश की कार्य संस्कृति में मूलभूत बदलावों की जरूरत है ताकि वैश्विक कंपनियों से मुकाबला किया जा सके। उनकी मानसिकता है कि भारतीय कर्मचारी काम से कम अपने देश में कम पेशेवर होते हैं। इस धारणा के मुताबिक भारतीय कर्मचारियों की आदत कामचोरी की होती है। वे आदतन आलसी होते हैं। देश के ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में ये दृश्य बेहद आम रहे हैं कि कर्मचारी या तो वक्त पर दपतर नहीं आते या फिर पूरे दिन अपनी टेबल से गायब रहते हैं। यही वजह है कि अब ज्यादातर सरकारी कार्यालयों और सरकारी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने की बायोमीट्रिक प्रणाली और कामकाज के आकलन के लिए उनके सालाना मूल्यांकन (अप्रैजल वाली) व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। बड़ी निजी कंपनियों में इससे ज्यादा सख्ती का माहौल है। कामकाज के सख्त मानकों को लागू करने के संबंध में नारायणमूर्ति के

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की

गया है। यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अब घरेलू हिंसा के मामलों में पीडित महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। शादी के वादे के झप्से में फसाकर शारीरिक संबंध बनाने पर अब तीन साल तक माना जाता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नए कानून का दुरुपयोग न हो। संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कड़ा कर दिया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा बढ़ा दी गई है। साथ ही, कुछ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान जोड़े हैं। बाल यौन शोषण

क्यानों का समर्थन कई और कंपनी-प्रमुखों ने किया है। उनकी दलील रही कि नारायणमूर्ति कामकाजी माहौल की थकान नहीं, बल्कि समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो हम पश्चिमी देशों की उस कार्य संस्कृति को अपना मानक नहीं बना, जहां हफ्ते में चार या पांच दिन या कम समय काम करना पड़ता है। यह देखते हुए कि भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम उत्पादक देशों में एक है, हमें अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो हम उन पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है। सिर्फ काम को अहमियत देने और कामकाज-जीवन संतुलन को तिलांजलि देने वाले इस फॉर्मूले को ताक पर रखने वाली इस कार्य संस्कृति के समर्थकों को ऑस्ट्रेलिया जैसी व्यवस्थाएं भी नागवार गुजरती हैं जहां दपतर से घर आने के बाद फोन या ईमेल का जवाब देने की जरूरत राइट-टू-डिस्कनेक्ट के अधिकार के तहत महसूस नहीं की जाती। पश्चिमी देशों में कुछ अंतर और हैं। जैसे, वहां किसी भी नौकरी या व्यवसाय के तहत काम के घंटों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है, जिससे कर्मचारी की निजी और सामाजिक जीवनशैली नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। वर्क-लाइफ बैलेंस कायम रखने

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की

के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, बाल पोर्नोग्राफी को एक गंभीर अपराध माना गया है। बाल तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बाल तस्करों को कठोर सजा दी जाएगी। बाल श्रम और बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुक्त कराए बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारत में बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह संहिता बच्चों को अपराध और बच्चों को शोषण से बचाने में मदद करेगी। संहिता में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। बीएनएस ने साइबर अपराधों की परिभाषा को विस्तृत किया है, जिसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन ९ गोष्वाध, साइबर उत्पीड़न और अन्य प्रकार के साइबर अपराध शामिल



की नीति के अंतर्गत यूरोपीय-अमेरिकी देशों में सरकारें और निजी कंपनियां यह हिसाब-किताब भी रखती हैं कि कहीं कर्मचारी ने साल में जरूरत से कम छुट्टियां तो नहीं लीं। या फिर कर्मचारी आवश्यकता से अधिक समय दपतर में तो नहीं रुक रहा है। हालांकि आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने भारत स्थित अपने कार्यालयों में पश्चिमी देशों वाला कामकाजी मॉडल अपनाने का मामला आया है, तो यहां वे इससे कन्नी काटने लगी हैं। संभव है कि वजह यह है कि भारत में श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को ज्यादा अफि ाकार नहीं मिले हैं। एक आकलन के अनुसार 50 साल पहले भारतीयों को एक हफ्ते में औसतन 39 घंटे काम करना होता था, लेकिन अब वह औसत बढ़कर 45 घंटे हो चुका है। दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की

हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के साइबर अपराधों को कानून के दायरे में लाया जा सके। बीएनएस ने साइबर अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है। इसमें लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना शामिल है। इसमें साइबर अपराध सिंडिकेट बनाने और चलाने के लिए दंड का प्रावधान शामिल है। बीएनएस में साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रावधान है। इससे साइबर अपराधों की जांच में दक्षता आएगी और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। बीएनएस में साइबर सुरक्षा के लिए उपाय करने का प्रावधान है। इसमें महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने, साइबर हमलों से बचाव करने और साइबर सुरक्षा जागरूकता विस्तार के उपाय शामिल हैं। संहिता में आतंकवाद से निपटने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए

हैं। संहिता में आतंकवाद की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रमुता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कार्य शामिल हैं। संहिता में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय प्रणाली में गति ला सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमानत की शर्तों को आसान बनाया गया है ताकि बेगुनाह लोग जेल में लंबा समय न बिताएं। निश्चित रूप से यह सकारात्मक कदम भारतीय न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की

हैं। संहिता में आतंकवाद की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रमुता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कार्य शामिल हैं। संहिता में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय प्रणाली में गति ला सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमानत की शर्तों को आसान बनाया गया है ताकि बेगुनाह लोग जेल में लंबा समय न बिताएं। निश्चित रूप से यह सकारात्मक कदम भारतीय न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की



खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने एक साक्षात्कार में बताया था कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने नियाद नैल्लनार योजना लागू की है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है श्वापका अच्छा गांवश्र । उन्होंने कहा था कि इस योजना के तहत हम लगातार सुरक्षा शिविर खोल रहे हैं। अब तक 34 सुरक्षा शिविर खोले गए हैं, जिनमें लगभग 96 गांव शामिल किए गए हैं। इन गांवों में सड़क, प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्य्ा रा से जोड़ना था। इससे पहले 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा था कि विकास ही उग्रवाद को

अच्छी बात है कि मुख्यधारा से कटे इलाकों तक भी सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नक्सलवाद क्यों बरकरार है, और इस सवाल पर गंभीरता से अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है। नक्सली अपनी समानांतर सत्ता स्थापित करने और सरकार से विरोध जताने के लिए निर्दोष नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों को निशाने पर लेते रहे हैं। उनका यह हिंसक रवैया किसी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि न स्थानीय नागरिक न जवान सरकारी नीतियां बनाते हैं या सरकार चलाते हैं। वे केवल अपनी कर्तव्य निभाते हैं। वहीं सरकारें भी नक्सलियों को खत्म करने के नाम पर जो ऑपरेशन चलाती हैं, उनमें निर्दोष लोगों की बलि कई बार चढ़ती है। मुठभेड़ों के नाम पर मासूम ग्रामीण चपेट में आ जाते हैं। यह सिलसिला कई बरसों से चल रहा है और जब मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग इन पर सवाल करते तो उन्हें देशद्रोही करार देने में गुरेज नहीं किया जाता। लेकिन न ग्रामीण आदिवासियों का शोषण रुका, न जेल, जंगल, जमीन पूंजीवाद के निशाने से बच रहे हैं और सैकड़ों जवानों की शहादत, अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। हालात तभी सुखेरे, जब दोनों पक्षों या सरकार चलाते हैं। वे केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। वहीं सरकारें भी नक्सलियों को खत्म करने के नाम पर जो ऑपरेशन चलाती हैं,

रामगढ़ शेखावादी में हुआ कला कुंभ का आयोजन राजस्थान दैनिक देश की उपासना

—कवि हरीश शर्मा ने बेटा पढ़ाओ—संस्कार सिखाओ अभियान पर आधारित कविता का किया काव्य पाठ, कवि योगेश वशिष्ठ ने औज काव्य पाठ तो हास्य कवि प्रमोद झुरिया ने अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को किया लॉटपोट, गिरधारी, रमेश ने मायड़ भाषा व शरद, बुद्धिप्रकाश आदि ने किया काव्य पाठ।

रामगढ़ शेखावादी। नववर्ष के उपलक्ष्य पर रामगढ़ शेखावादी की धरती पर किस्सेदारियों परिवार ने राष्ट्रीय कवि संगम और शेखावादी साहित्य संगम के सहयोग से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत विद्यालय में "कला कुंभ" नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र साहित्य वार्ता में लेखक वक्ता अमित झालानी ने सभी उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। द्वितीय सत्र में वरिष्ठ कवि योगेश वशिष्ठ ने औज काव्य पाठ किया, वहीं वरिष्ठ कवियों की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए गिरधारी, रमेश ने मायड़ भाषा में काव्य पाठ किया, शरद, बुद्धिप्रकाश आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में लक्ष्मणगढ़ के कवि हरीश शर्मा ने किस्सेदारिया मंच को समर्पित पौं बाबूजी के जाने के बाद बच्चों पर आ जाती है घर की जिम्मेदारिया और आज जिस मंच ने मुझे जगह दी है उसका नाम है किस्सेदारिया से शुरुआत करते हुए बेटा पढ़ाओ—संस्कार सिखाओ अभियान, दादी माँ की मार्मिक कविता एवं



पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हास्य कवि प्रमोद झुरिया ने अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लॉटपोट किया। उभरते कवियों और शायरों ने कार्यक्रम को और भी रोचक बनाया, जिनमें कृष्ण कांत बटोही, भगवती पारीक "मनु", ऋतु, दिनेश, लवकी सांखला, प्रियंका चौहान, कैमी राजपूत, रचना, प्रियंका और अन्य कई कवियों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निखिल, मोहित, कृष्ण प्रजापत और अन्य नए संगीतकारों ने अपने गायन और वाद्य यंत्रों से चार चांद लगाए। साथ ही कृतिका बजाज, हर्षिता

लोसनिया और कुछ अन्य कलाकारों ने कला प्रदर्शनों के माध्यम से चित्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। मंच का कुशल संचालन किया। दिनेश भारती द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का आयोजन में कश्मिरिया परिवार के गोकुल भारती, खुशवंत शर्मा, कृष्ण कांत बटोही और शिवम ने किया। रामगढ़ शेखावादी और शेखावादी अंचल के विभिन्न स्थानों के गण मान्यजनों ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर संजय हरितवाल, विष्णु शर्मा, राहुल सैनी खूड़ी, चंदन पुजारी, अर्जुन शर्मा भी मौजूद रहे।

अंचल प्रमुख महाप्रबंधक रंजीव कुमार ने केनरा बैंक की एंजेल योजना के विषय पर विस्तार से ग्राहकों को समझाया



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। अंचल प्रमुख महाप्रबंधक रंजीव कुमार ने केनरा बैंक की एंजेल योजना के विषय पर विस्तार से ग्राहकों को समझाते हुए कहा कि केनरा बैंक की नींव उनकी ग्राहक सेवा पर आधारित है। केनरा बैंक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ-1 द्वारा बैंक के

प्रोमियम ग्राहकों के मध्य होटल दयाल पैराडाइज गोमती नगर में किया गया, जिसके बाद डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। केनरा बैंक ग्राहकों को समझाते हुए कहा कि केनरा बैंक की नींव उनकी ग्राहक सेवा पर आधारित है। केनरा बैंक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ-1 द्वारा बैंक के

प्रोमियम ग्राहकों के मध्य होटल दयाल पैराडाइज गोमती नगर में किया गया, जिसके बाद डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। केनरा बैंक ग्राहकों को समझाते हुए कहा कि केनरा बैंक की नींव उनकी ग्राहक सेवा पर आधारित है। केनरा बैंक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ-1 द्वारा बैंक के

‘उद्यान विभाग द्वारा एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन’

‘रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव’ हरदोई जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्र ने बताया है कि विगत दिवस जनपद में संचालित पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरीगेशन) योजनान्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र बावन रोड, हरदोई के प्रशिक्षण केन्द्र पर 50 कृषकों के समूह का एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डा० ए०के० तिवारी, वैज्ञानिक डा० डी०बी० सिंह, डा० प्रिया वशिष्ठ, एग्रोनॉमिस्ट (रिवुलिस इरीगेशन) आशुतोष सिंह एवं इंजीनियर अतुल चौधरी, उपस्थित रहे। इसी के साथ जनपद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मूल्यांकन हेतु उ०प्र० शासन से आई टीम के सदस्य

आलोक जायसवाल, ए०एस०ओ०, दीपचन्द्र आर्य, ए०डी०एस०टी०ओ०, अश्वनी मिश्रा, ए०एस०ओ० नियोजन अनुभाग ने भी प्रशिक्षण में आये कृषकों से प्रश्नोत्तरी एवं साक्षात्कार किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि कृषक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर भू-जल का संचयन कर सकेंगे साथ ही पौधों की सिंचाई पर उपयोग होने वाली मात्रा का सदुपयोग कर गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और लागत में कमी लाकर अपनी उपज से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। आशुतोष सिंह, एग्रोनॉमिस्ट

(रिवुलिस इरीगेशन) द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यक्रम में आये कृषकों को ड्रिफ्टस्प्रिंकलर विधि से सिंचाई के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा भी कृषकों को सिंचाई पद्धति, बीजों की बुवाई, फर्टीगेशन विधियों, कीटों से फसलों के बचाव आदि से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कृषक इस विधि का प्रयोग कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है। प्रशिक्षण में आये प्रत्येक कृषक को प्रशिक्षण बैग, पेन, पैड, तकनीकी साहित्य वितरित किये गये। अन्त में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

‘गौसेवा के भाव के साथ गोवंश संरक्षण के मिले अच्छे परिणाम – जिलाधिकारी’



‘रिपोर्ट—जनार्दन श्रीवास्तव’ हरदोई जनपद के पशुपालन विभाग का गोवंश के साथ भावनात्मक रिश्ता उस समय दिखा जब उन्होंने गोवंश को टण्ड से बचाने के लिए नये बछड़ों को अपने पुराने कपड़े

पहनाये। नये बछड़ों को टण्ड से बचाने का यह नायाब तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गोसेवा के भाव के

साथ गोवंश संरक्षण के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके साथ ही जनपद की गौशालाओं में अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। गोवंश को टाट से बनी झूल भी उड़ाई जा रही है। कुछ गौशालाओं में हीटर की भी व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी ने पिछले दो वर्षों के दौरान गौशालाओं पर विशेष ध्यान दिया है। गौशालाओं की व्यवस्थाओं में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। कंट्रोल रूम से लगातार गौशालाओं की निगरानी हो रही है। गोवंश संरक्षण में जनपद हरदोई ने अन्य जनपदों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।

पीयूष बंसल ने 5 करोड़ रुपये में एनओओई की नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। शार्क टैंक इंडिया 4 में दर्शकों को उस वक़्त एक ऐतिहासिक पल देखने का मौका मिला, जब पीयूष बंसल ने शो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चेक लिखा। उन्होंने प्रीमियम लाइफस्टाइल और एसेसरी ब्रांड एनओओई में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद ली। यह महत्वपूर्ण निवेश भारतीय स्टार्टअप पर शो के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। पीयूष सूरी और नितिका पांडे द्वारा शुरू किया गया एनओओई अपने स्टूडियो और पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। इस ब्रांड को प्रतिष्ठित रेड डॉट डिजाइन अवार्ड जैसे सम्मान मिल चुके हैं और यह अब 9 देशों में मौजूद है। एनओओई एक बहुत ही खास नाम है और इसे जेवर ऑड और इवेन वाक्य से लिया गया है। यह वाक्य उल्टा पढ़ने पर भी वही रहता है, इसे पैलेट्रॉम कहते हैं। यह नाम इस बात को दिखाता है कि एनओओई सभी लोगों को एक जैसा

मानती है और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। जब पीयूष ने इस कंपनी के बारे में सुना तो वे इसके नए उत्पादों और दुनिया के अलग-अलग देशों में फैलने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। हालांकि, साथी शार्क अमन गुप्ता ने मजाक में पीयूष को ज्यादा हिस्सेदारी रखने की सलाह दी, लेकिन 5 करोड़ रुपये में 51: इक्विटी का ऑफर फाउंडर्स के लिए बेहद आकर्षक साबित हुआ। एनओओई के को-फाउंडर पीयूष सूरी ने डील पर अपनी खुशी का इजहार करते हुये कहा, "यह सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक रोमांचक सफर की शुरुआत है। 'शार्क टैंक इंडिया' जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारे जैसे व्यवसायों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का मौका दिया है। पीयूष का निवेश एनओओई के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, और हम उन्हें अपने सझेदार के रूप में पाकर बेहद उत्साहित हैं। उनकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन के साथ, हमें विश्वास है कि एनओओई नई ऊंचाइयों को

छुएगा और अनगिनत उद्यमियों को अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।" शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 ने शार्कस का एक शानदार पैनल बनाया है। इनमें शामिल हैं पीपुल युपके फाउंडर और सीईओ अनुपम मित्तल, बोट लाइफस्टाइल के को-फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता, एम्बयोर फार्मास्युटिकल्स की एकजीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, ओयो के फाउंडर और ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल, लेंसकार्ट के को-फाउंडर और सीईओ पिपूष बंसल, शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह, इनशॉर्ट्स के को-फाउंडर और चेयरमैन अजहर इकबाल, एको के फाउंडर और सीईओ वरुण दुआ, स्नैपडील और टाइटन कैपिटल के को-फाउंडर तथा यूनिफॉर्मस के प्रमोटर कुणाल बहल और वीबा वीआरबी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विराज बहल। देखिये शार्क टैंक इंडिया 4, हर सोमवार से शुक्रवार, रात 8 बजे, सिर्फ सोनी लिव पर!



अपोलोमेडिक्स अस्पताल ने दुर्लभ सर्जरी द्वारा 14 वर्ष बाद खोले जुड़े हुए जबड़े, पहली बार युवक ने खाया खाना

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में एक दुर्लभ और जटिल सर्जरी द्वारा 14 साल से बंद पड़े जबड़े को खोलकर मरीज को एक नई जिंदगी दी। बचपन की चोट के कारण रोगी का मुंह 5-6 साल की उम्र से ही पूरी तरह बंद था और उसके जबड़े आपस में जुड़ से गए थे जिस कारण रोगी पिछले 14 वर्षों से न ही खाना खा पा रहा था और न ही सही ढंग से कुछ बोल पा रहा था। यह चुनौतीपूर्ण सर्जरी अस्पताल के प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के डायरेक्टर और प्रमुख डॉ. सुमित मल्होत्रा और प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट डॉ. सौरभ मोहिंद्र की टीम ने की। डॉक्टर सुमित मालहोत्रा ने मीडिया को इस मामले के बारे में बताते हुए कहा, प्संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 वर्षीय आदित्य पिछले 14 वर्षों से बंद जबड़े के साथ हमारे

अस्पताल आए थे जो पिछले 14 वर्षों से कोई ठोस भोजन नहीं खा पा रहे थे और पूरी तरह से तरल आहार पर थे। इसने उनके विकास और बोलने की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। रोगी ने बहुत से अस्पतालों में दिखाया लेकिन उसे कोई संतोषजनक उपचार नहीं मिल सका। यह मरीज हमारे पास डेंटल साइंसेज विभाग में आया। जांच में पाया गया कि बचपन में लगी चोट के कारण उसका टेम्पोरल मैडिबल जॉइंट (ज्मउचवतंस डंदकपइसम श्रवपदज) क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते जबड़ा पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद मरीज को प्लास्टिक सर्जरी विभाग में रेफर किया गया, जहां हमारी टीम ने अत्याधुनिक 'मसल प्लेप' तकनीक का उपयोग करके इस बंद जोड़ का उपचार किया। इस तकनीक द्वारा जबड़े की नसों में सक्रिय रक्त आपूर्ति के साथ मांसपेशियों को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि जबड़े का



जोड़ फिर से न जुड़ने पाए। यह प्रक्रिया, जो उत्तर भारत में बहुत ही कम होती है, एक अत्यंत जटिल सर्जरी है। डॉ. मल्होत्रा ने आगे बताया, "हमारी तकनीक ने सुनिश्चित किया कि मरीज का जबड़ा सामान्य रूप से कार्य करे और भविष्य में इसमें कोई जटिलता न पैदा हो।" डॉ. सौरभ मोहिंद्र ने कहा, "सर्जरी के बाद, मरीज 14 वर्षों में पहली बार ठोस भोजन जैसे रोटी आदि खाने में सक्षम हुआ। सर्जरी से उसकी मुंह खोलने

शुरुआत में मरीज को मुंह खोलने में असुविधा या हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास से लचीलापन और ताकत पूरी तरह से वापस आ जाएगी और उनका जबड़ा पहले की तरह सामान्य रूप से कार्य कर पायेगा। डॉ. मयंक सोमानी, एमडी और सीईओ, अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने कहा, प्यह सर्जरी केवल एक चिकित्सकीय सफलता नहीं है, बल्कि मरीज के लिए जीवन को बेहतर बनाने वाला एक अनुभव है। इससे न केवल उसकी कार्यक्षमता बल्कि आत्मविश्वास भी वापस आया है, जिससे वह एक सामान्य जीवन जीने में सक्षम हुआ है। सर्जरी के बाद जब मरीज ने पहली बार भोजन का स्वाद चखा, तो यह उसके और उसके परिवार के लिए बहुत भावुक क्षण था। यह हमारी टीम की एक बड़ी उपलब्धि है। यह केस हमारे द्वारा मरीजों की पूरी देखभाल और इलाज में नई तकनीकों के प्रयोग के हमारे प्रयासों का उदाहरण है।

इंडियन बैंक के लखनऊ अंचल प्रबंधक प्राणेश कुमार एवं पराग लखनऊ मंडल अध्यक्ष शिखा सिंह तोमर ने एमओयू का आदान-प्रदान किया



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। लखनऊ पराग मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम

में इंडियन बैंक की ओर से दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के लिए तैयार किए गए विशेष डिजिटल उत्पाद

औपचारिक रूप से एमओयू का हस्ताक्षर उपरांत आदान-प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में पराग मंडल की ओर से महाप्रबंधक विकास बाल्यान एवं इंडियन बैंक की ओर से लखनऊ अंचल प्रबंधक प्राणेश कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। जिसकी प्रति अंचल प्रबंधक लखनऊ प्राणेश कुमार एवं पराग मंडल अध्यक्ष शिखा सिंह तोमर ने एक दूसरे को प्रदान की। इस कार्यक्रम में लखनऊ पराग अधिकारी नीलेश श्रीवास्तव तथा पराग सुपरवाइजर सहित इंडियन बैंक मवई शाखा प्रबंधक अमित वर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इंडियन बैंक लखनऊ के अंचल प्रमुख श्री प्राणेश कुमार ने

अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर राज्य है। इस स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में इंडियन बैंक भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। डॉ. उन्होंने कहा कि इस एमओयू के द्विपक्षीय निष्पान से हम अपने कृषक ग्राहकों को, जो कि पराग प्लांट में दुग्ध उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें डिजिटल माध्यम से रु. 2 लाख तक कृषि ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) बिना किसी कोलेटरल शीवास्तव तथा पराग सुपरवाइजर सहित इंडियन बैंक मवई शाखा प्रबंधक अमित वर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इंडियन बैंक लखनऊ के अंचल प्रमुख श्री प्राणेश कुमार ने

ता कराने में सहयोग प्रदान किया जा सके। अंचल प्रबंधक श्री प्राणेश कुमार ने पराग अधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी कुल 1081 शाखाएं, 536 एटीएम, 434 बी सी लोकेशन तथा 6469 दूध पॉइंट का विस्तृत नेटवर्क है। डॉ. प्राणेश ने कहा कि इंडियन बैंक में ग्राहकों आवश्यकता के अनुसार डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि हम ग्राहकों को प्रभावशाली और त्वरित सेवा दे सकें। मुख्य महाप्रबंधक लखनऊ सुधीर कुमार गुप्ता ने एमओयू की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं एवं सभी किसानों को इसका बढचढ कर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

फॉर्मर रजिस्ट्री की संख्या में जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) नये वर्ष की शुरुआत में जब से फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मोर्चा संभाला है तब से इस कार्य में एक अभूतपूर्व तेजी देखी गयी। दैनिक प्रगति की बात की जाये तो नये वर्ष के पहले दिन से ही जनपद लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। फॉर्मर रजिस्ट्री की कुल संख्या के मामले में जनपद अब प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। इसके लिए एक ओर जहाँ किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। कार्य में लगे कर्मचारियों में लगातार जोश भरने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर्स के संचालक भी लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाये तथा लापरवाह कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाये।

फॉर्मर रजिस्ट्री की संख्या में जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। लखनऊ सिविल डिफेंस में और तेजी लाने के लिए अगले तीन महीने में प्रखंड चौक में एक हजार नए फायर फाइटर की भर्ती की जाएगी। ये बात लखनऊ सिविल डिफेंस के सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मनोज वर्मा ने एक बैठक के दौरान कही। उपनिर्यंत्रक अनिता प्रताप की उपस्थिति व चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा के नेतृत्व में लखनऊ सिविल डिफेंस अपने कार्यों से नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में सिविल डिफेंस लखनऊ के प्रखंड चौक की नव वर्ष पर कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में अगले तीन महीने में एक हजार नए फायर फाइटरों की भर्ती का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति पदक से अलंकृत लखनऊ सिविल डिफेंस के सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मनोज वर्मा ने बताया कि नववर्ष 2025 पर प्रखंड चौक की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डनों ने प्रतिभा दिया। बैठक के दौरान प्रखंड की गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए नए और युवा फायर फाइटर भर्ती करने पर चर्चा की गई। प्रखंड के



डिविजनल वार्डन सुनील कुमार शुक्ला ने पुराने और निष्क्रिय फायर फाइटर के स्थान पर नए फायर फाइटर की भर्ती पर सहमति जताई। जिसके बाद बैठक में उपस्थित समस्त वार्डनों को निर्देश दिए गए कि योजनाबद्ध तरीके से अगले तीन महीने में एक हजार नए फायर फाइटरों की भर्ती करना सुनिश्चित करें। जिसके लिए प्रखंड के सभी दस पोस्ट वार्डन अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में संपर्क करें। सुनील शुक्ला ने सेक्टर वार्डनों से कहा कि वो लक्ष्य के अनुरूप अपने

सेक्टर में 15 वर्ष से ऊपर के व शारीरिक रूप से मौजूद लड़के और लड़कियों को सिविल डिफेंस से जुड़ने हेतु प्रेरित कर फायर फाइटर के रूप में भर्ती करने के अभियान में जुट जाएं। नववर्ष पर आयोजित प्रथम बैठक में प्रखंड के डिप्टी डिविजनल वार्डन जावेद जैदी, जगदीश यादव, घटना नियंत्रण अधिकारी सईद अख्तर, पोस्ट वार्डन इस्मर अहमद, रिश्ता पटेल, अमर कुमार, मनोज तिवारी, सुनील शुक्ला ने सेक्टर वार्डनों से कहा कि वो लक्ष्य के अनुरूप अपने

